राजबीर सेहरावत, जे.

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड और अन्य- अपीलार्थी

बनाम

जेस्वांट @जेएआईबीआईआर प्रतिवादी

आरएसए नंबर **3933** साल **2017**

30 अगस्त, 2017

ए. विद्युत अधिनियम, 2003- धारा. 126,135 और 145- बिजली की चोरी- आकलन/जुर्माना- दीवानी न्यायालय का अधिकार क्षेत्र-आयोजित, जहां उपभोक्ता ने चोरी की है और कार्यवाही शुरू की गई है, मूल्यांकन अधिकारी को दायित्व और जुर्माने के आकलन के संबंध में कोई आदेश पारित करने का कोई अधिकार नहीं है और यदि ऐसा कोई आदेश किसी उपभोक्ता के खिलाफ पारित किया जाता है तो उपभोक्ता को दीवानी मुकदमे का उपचार प्राप्त करने का पूरा अधिकार है।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि यदि विभागों/ अधिकारियों/लाइसेंसधारी/आपूर्तिकर्ता की राय है कि किसी उपभोक्ता ने अधिनियम के तहत परिभाषित चोरी की है, और वे अधिनियम की धारा 135 के तहत चोरी के लिए कार्यवाही शुरू करते हैं, तो मूल्यांकन अधिकारी को उपभोक्ता के खिलाफ दायित्व और दंड के आकलन के संबंध में कोई आदेश पारित करने का कोई अधिकार नहीं है। यदि

मूल्यांकन/जुर्माने का ऐसा कोई आदेश पारित किया जाता है और विभाग/लाइसेंसधारी/आपूर्तिकर्ता द्वारा किसी उपभोक्ता के खिलाफ कथित रूप से लागू किया जाता है, तो उपभोक्ता को विभाग/लाइसेंसधारी/आपूर्तिकर्ता द्वारा उठाए गए ऐसे आदेश/मांग को चुनौती देकर दीवानी मुकदमे का लाभ उठाने का मुकदमा अधिकार है। ऐसी स्थिति में, दीवानी न्यायालय की अधिकार क्षेत्र अधिनियम की धारा 145 के आधार पर बाधित नहीं होगी। (पैरा 37 (1)

ख. विद्युत अधिनियम, 2003- विशेष न्यायालय की शक्ति- विशेष न्यायालय निहितार्थ से, सिविल न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बाहर नहीं करता है, ऐसे मामले में जहां निर्धारण अधिकारी ने अनधिकृत रूप से मांग का आदेश पारित किया हो।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि चूंकि उपभोक्ता के आग्रह पर विशेष न्यायालय की शुरुआत नहीं की जा सकती है और विशेष अदालत द्वारा निर्धारित नागरिक दायित्व को केवल उपभोक्ता के खिलाफ और केवल विभाग को हुए नुकसान/नुकसान के लिए निर्धारित करने के लिए प्रतिबंधित किया गया है और यहां तक कि एक दीवानी अदालत की प्रक्रिया का पालन किए बिना भी, इसलिए, केवल विशेष न्यायालय का अस्तित्व, निहितार्थ से, दीवानी न्यायालय की अधिकार क्षेत्र को बाहर नहीं करता है, ऐसे मामले में जहां निर्धारण करने वाला अधिकारी/लाइसेंसधारी/आपूर्तिकर्ता ने मामले को पुलिस या विशेष अदालत

को भेजने के बावजूद अवैध या अनधिकृत मांग का आदेश पारित किया है। (पैरा 37 (3)

पवन कुमार लोंगिया, अधिवक्ता

अपीलार्थियों के लिए।

राजबीर सहरावत, जे।

(1) अदालत द्वारा विचार के लिए इस अपील में शामिल एकमात्र सवाल यह है कि क्या सिविल कोर्ट का अधिकार क्षेत्र भारतीय बिजली अधिनियम की धारा 145 के तहत वर्जित है, उन मामलों में जहां बिजली बोर्ड/विभाग की मांग बिजली अधिनियम की धारा 135 के तहत कथित चोरी के आधार पर शुल्क की है और आगे क्या उपभोक्ता को ऐसे मामले में अधिनियम की धारा 127 के तहत अपील का वैकल्पिक उपाय सुझाया जा सकता है।

(2) इस मामले के तथ्य यह हैं कि प्रतिवादी ने यहां इस आशय के स्थायी और अनिवार्य निषेधाज्ञा के लिए एक मुकदमा दायर किया था कि प्रतिवादियों को उनके परिसर में स्थापित मीटर की बिजली आपूर्ति को काटने से रोका जाए और उन्हें रुपये के आक्षेपित जुर्माने की वसूली से भी रोका जाए। जो प्रतिवादी संख्या 1 (यहाँ अपीलार्थी) द्वारा दिनांकित ज्ञापन 27.01.2006 के माध्यम से लगाया गया था।वादी/प्रत्यर्थी द्वारा यहाँ यह निवेदन किया गया था कि उसके पास अट्टा चक्की का घरेलू बिजली

कनेक्शन था जिस पर नंबर था। 1982 से गाँव मातरशम तहसील और जिला हिसार में अपने परिसर में एम-18एसपी।15.01.2006 पर उपरोक्त विद्युत मीटर में बिजली की किसी खराबी/वोल्टेज में उतार-चढ़ाव के कारण आग लग गई और मीटर जल गया।अभियोक्ता के पड़ोसी नंद लाल ने मीटर को जलते हुए देखा था और अभियोक्ता को इसके बारे में सूचित किया था।पड़ोस के लोग, यहाँ तक कि गाँव के सरपंच और पंच भी वहाँ जमा हो गए।अभियोक्ता अपने चाचा के साथ क्षेत्र के लाइनमैन को गाँव कुर्री में सूचित करने गया।लेकिन लाइनमैन उपलब्ध नहीं था और फिर एक और लाइन-मैन गाँव में आया और उसने स्थल का निरीक्षण किया और अभियोक्ता को आदमपुर क्षेत्र के जे. ई. को मामले की रिपोर्ट करने के लिए कहा।इसके बाद उक्त जे. ई. को मामले की सूचना दी गई।आई. डी. 1 की सुबह जे. ई. ने आकर स्थल का निरीक्षण किया था और उसी दिन लिखित में एक आवेदन दिया गया था जो प्रतिवादियों के शिकायत रजिस्टर में दर्ज किया गया था।इसके बाद, प्रतिवादियों ने अभियोक्ता से एक नया मीटर खरीदने के लिए कहा और नया मीटर एक मध्यस्थ चाय विक्रेता द्वारा से खरीदा गया, जो प्रतिवादियों के कार्यालय के बाहर चाय की दुकान पर था।उनसे 2,100/- रुपये की राशि ली गई और नए मीटर को 17.01.2006 पर ही परीक्षण के लिए प्रयोगशाला में भेजा गया था।

(3) शिकायत में आगे यह दलील दी गई कि कपूर सिंह जे. ई. ने अभियोक्ता को बताया कि उसका कनेक्शन अट्टा चक्की चला रहा था और

इसलिए, एस. डी. ओ., अवनीत सिंह और एक राय साहब अभियोक्ता से <आई. डी. 1,000/- की मांग कर रहे हैं और यदि उनके द्वारा भुगतान नहीं किया जाता है तो उसके खिलाफ बिजली की चोरी का मामला दर्ज किया जाएगा।अभियोक्ता ने उपरोक्त कपूर सिंह से अनुरोध किया कि जब मीटर जला दिया गया था तो उनकी कोई गलती नहीं थी।यह आगे दलील दी गई कि उपरोक्त डी अन खटकर ने 19.01.2006 पर गाँव में आया, धमकी दी और रुपये की माँग की। 25, 000/- अभियोक्ता से।अभियोक्ता भयभीत हो गया और रुपये का भुगतान किया। 12, 500/- कपूर सिंह, जे. ई. को राम प्यारा और मुंशी राम की उपस्थिति में और 500/- लेने के बाद कपूर सिंह ने अभियोक्ता को हिसार कार्यालय जाने के लिए कहा और वहां कुछ मुद्रित कागजों पर अभियोक्ता के हस्ताक्षर प्राप्त किए गए।इसके बाद, कपूर सिंह ने धमकी दी कि अगर आईडी1,500/- की शेष राशि का भुगतान नहीं किया गया तो वह असहाय हो जाएगा क्योंकि उपरोक्त व्यक्ति रिश्वत की पूरी राशि की मांग कर रहे थे।अभियोक्ता ने अधिक भुगतान करने में असमर्थता व्यक्त की।इसके बाद, अधिकारियों द्वारा एक झूठी रिपोर्ट तैयार की गई कि मीटर की एम और पी मुहर गायब पाई गई और रिवेट्स के साथ छेड़छाड़ की गई।अभियोक्ता ने दावा किया कि न तो मीटर से छेड़छाड़ की गई और न ही सील से छेड़छाड़ की गई।बिजली आपूर्ति/वोल्टेज में उतार-चढ़ाव के कारण मीटर जल गया था।28.01.2006 पर, अभियोक्ता को 27.01.2006 दिनांकित एक पत्र प्राप्त हुआ जिसके द्वारा रु. 1,49,200-का जुर्माना लगाया गया था।(4) यह भी दलील दी

गई कि इस अवैध मांग को चुनौती देते हुए अभियोक्ता ने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण मंच, हिसार (संक्षेप में, 'फोरम') का रुख किया था।फोरम ने प्रतिवादियों की ओर से सेवा में कमी और लापरवाही को माना और शिकायतों को स्वीकार कर लिया गया और 19.01.2006 की जाँच रिपोर्ट और 27.01.2006 के जुर्माने के बारे में नोटिस को रद्द कर दिया गया और प्रतिवादियों को अभियोक्ता के परिसर में अट्टा छकी की बिजली आपूर्ति बहाल करने का निर्देश दिया गया।तथापि, अपील पर राज्य उपभोक्ता आयोग ने अभिनिर्धारित किया कि अभियोक्ता उपभोक्ता की परिभाषा में नहीं आता है, इसलिए फोरम द्वारा पारित आदेश को उलट दिया गया।नतीजतन, अभियोक्ता को जुर्माने के अवैध आदेश को चुनौती देते हुए दीवानी मुकदमे में आना पड़ा और बिजली आपूर्ति को काटने के खिलाफ निषेधाज्ञा की भी मुकदमा करनी पड़ी।

(5) इस बीच, अभियोक्ता के खिलाफ पुलिस स्टेशन सदर हिसार, में बिजली चोरी का मामला दर्ज किया गया। अभियोक्ता को मामले में अग्रिम जमानत दी गई थी।इसके बाद, अभियोक्ता ने उपरोक्त डी अन खटकर और कपूर सिंह आदि के खिलाफ 08.04.2006 पर आपराधिक शिकायत भी दर्ज कराई थी।यह एक और बात है कि इस शिकायत को बाद में अदालत ने खारिज कर दिया था। हालाँकि, बिजली की चोरी से संबंधित प्राथमिकी आर. मामले में भी अभियोक्ता को आपराधिक अदालत ने बरी कर दिया था।

(6) मुक़दमे में अभियोक्ता द्वारा यह आदेश किया गया था कि सभी प्रतिवादियों ने एक-दूसरे की मुकदमा से, अभियोक्ता पर पैसे ऐंठने के लिए दबाव बनाने के लिए कहानी और 09.01.2006 और 22.01.2006 की जाँच रिपोर्ट गढ़ी।अन्यथा, इस मामले में बिजली की चोरी नहीं हुई थी।

(7) प्रतिवादी ने मामले में लिखित बयान दायर किया।यह आरोप लगाया गया था कि अभियोक्ता का एक छोटी श्रेणी का संबंध था।हालाँकि, वह इसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए कर रहा था।लिखित बयान में आगे यह प्रस्तुत किया गया कि अभियोक्ता ने स्वयं मीटर को जलाया ताकि उसके द्वारा मीटर की मुहर तोड़ने के सबूत को हटाया जा सके।

(8) यह भी दावा किया गया कि श्री द्वारा 19.01.2006 पर मीटर की जाँच की गई थी। D.N.Khattar, A.E.M&P, अभियोक्ता द्वारा बिजली की चोरी करने के संबंध में किसी अज्ञात व्यक्ति से टेलीफोन पर जानकारी प्राप्त करने के बाद।उक्त परिसर 19.01.2006 पर बंद पाया गया।जाँच के बाद, अभियोक्ता ने मीटर बदलने के लिए एसडीओ, ऑपरेशन, सब डिवीजन आदमपुर के कार्यालय में एक आवेदन दायर किया।एम एंड पी ने इच्छा व्यक्त की थी कि उक्त मीटर को एम एंड टी प्रयोगशाला को दिनांकित ज्ञापन 24.01.2006 के माध्यम से भेजा जा सकता है।24.01.2006 पर अभियोक्ता की उपस्थिति में प्रयोगशाला में अभियोक्ता के मीटर की जाँच की गई।जाँच के दौरान, मीटर की सभी एम एंड टी मुहरें गायब पाई गईं और दोनों रिवेट्स के साथ छेड़छाड़ की गई

और मीटर का मीटर ब्लॉक टर्मिनल जला हुआ पाया गया।इसलिए, यह बिजली की चोरी का एक स्पष्ट मामला होने का दावा किया गया था।यह आगे दावा किया गया कि भारतीय विद्युत अधिनियम की धारा 135,138,152 के तहत अभियोक्ता को दिनांक 27.01.2006 के ज्ञापन के माध्यम से अपराध के चक्रवृद्धि के लिए एक नोटिस दिया गया था, जिसमें जवाब देने वाले प्रतिअभियोक्ता ने अभियोक्ता को निगम को हुए नुकसान के लिए Rs.84,729/- की राशि जमा करने की आवश्यकता थी और आगे अभियोक्ता को अपराध के चक्रवृद्धि के लिए रु. 1,49,200 की राशि जमा करने की आवश्यकता थी।यह दावा किया गया था कि केवल अपनी त्वचा को बचाने के लिए अभियोक्ता शरारतपूर्ण आरोप लगा रहा था।प्रतिवादियों/अपीलार्थियों द्वारा यहां यह भी मुकदमा किया गया था कि दीवानी न्यायालय को मुकदमे की सुनवाई करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।

(9) दलों ने अपने-अपने साक्ष्य का नेतृत्व किया।

(10) साक्ष्य की सराहना करने और मुकदमाोें को सुनने के बाद, निचली अदालत ने मुकदमा खारिज कर दिया।विद्वत निचली अदालत द्वारा तैयार किया गया मुकदमा संख्या 3 मुकदमे का प्रयास करने और उस पर विचार करने के अधिकार क्षेत्र से संबंधित था।हालाँकि, जैसा कि विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किया गया है; इस मुद्दे को साबित करने की जिम्मेदारी प्रतिवादियों पर थी।लेकिन बहस के दौरान प्रतिवादियों के

विद्वान अधिवक्ता ने मुद्दे संख्या 2 से 5 पर जोर नहीं दिया था, जिसमें अधिकार क्षेत्र के संबंध में मुद्दा संख्या 3 शामिल था।विद्वत निचली अदालत ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि केवल इसलिए कि अभियोक्ता को आपराधिक न्यायालय द्वारा बरी कर दिया गया था जो अपने नागरिक अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए बिजली की चोरी के संबंध में अभियोक्ता के खिलाफ निष्कर्ष दर्ज करने के खिलाफ दीवानी अदालत को बाध्य नहीं करता है।

(11) विद्वत निचली अदालत द्वारा पारित निर्णय और डिक्री से व्यथित होकर अभियोक्ता ने अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, हिसार के समक्ष अपील दायर की।हिसार के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने अभियोक्ता द्वारा मुकदमा अपील को स्वीकार कर लिया और अभियोक्ता के मुकदमे का फैसला करने का आदेश दिया।प्रतिअभियोक्ता निगम को विवादित रिपोर्ट के आधार पर अभियोक्ता को बिजली की आपूर्ति काटने से रोक दिया गया था और जुर्माने के विवादित ज्ञापन के आधार पर कोई भी वसूली करने से भी रोक दिया गया था।साक्ष्य की सराहना करने के अलावा, विद्वत अपील न्यायालय ने यह भी दर्ज किया कि जब अभियोक्ता का मीटर 19.01.2006 पर नहीं हटाया गया था क्योंकि उसका परिसर बंद पाया गया था और दिनांक 24.01.2006 की संयुक्त जाँच रिपोर्ट से पहले अभियोक्ता ने प्रतिअभियोक्ता निगम को एक रिपोर्ट दी थी कि उसका मीटर जला दिया गया है तो किस आधार पर प्रतिअभियोक्ता आरोप लगा

रहे थे कि उन्होंने अभियोक्ता के परिसर में बिजली की चोरी का पता लगाया था।विद्वत अपील न्यायालय द्वारा आगे यह अभिलिखित किया गया कि ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिअभियोक्ता निगम के अधिकारी केवल अपने अधिकारियों के अवैध कार्यों को बचाने और अभियोक्ता को बिजली की चोरी के तथाकथित मामले में फंसाने के उद्देश्य से परेशान करने के लिए एक-दूसरे के साथ हाथ मिला कर काम कर रहे थे।जब अभियोक्ता के मीटर को प्रयोगशाला में भेजने से पहले जला दिया गया था, तो विभाग के साथ यह निष्कर्ष निकालने की स्थिति नहीं हो सकती थी कि मीटर की सटीकता को देखे बिना, बिजली की चोरी अभियोक्ता द्वारा की जा रही थी, विशेष रूप से जब जाँच रिपोर्ट में एक्सःडी-1 में यह उल्लेख किया गया है कि उन्हें अभियोक्ता के मीटर के जलने की शिकायत मिली थी।विद्वत अपील न्यायालय ने यह भी दर्ज किया है कि उनके समक्ष कोई अन्य तर्क नहीं दिया गया था।इससे यह भी पता चलता है कि अधिकार क्षेत्र के बारे में मुद्दा भी विद्वान अपील न्यायालय के समक्ष नहीं उठाया गया था।

(12) विद्वत अपील न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और डिक्री से व्यथित, प्रतिवादी इस न्यायालय के समक्ष अपील में आए हैं।प्रतिवादियों के अपील में आने का कारण इस न्यायालय के निर्णय प्रतीत होते हैं जिसमें कहा गया है कि दीवानी अदालत के पास बिजली की चोरी से संबंधित मामले की सुनवाई करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।

(13) मामले में बहस करते हुए, अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्क को केवल इस सवाल तक सीमित कर दिया है कि जब उपभोक्ता द्वारा बिजली की चोरी के कारण विभाग द्वारा खपत या जुर्माने के कारण नुकसान की वसूली की सूचना दी जाती है तो दीवानी अदालत को मामले की सुनवाई करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।अपने तर्क का समर्थन करने के लिए अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा किया है। मेसर्स भारत ऑटो केयर बनाम पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड और एक अन्य 1, U.H.B.V.N, पानीपत और अन्य बनाम विनोद कुमार 2 और इस न्यायालय द्वारा पारित और शीर्षक में रिपोर्ट किया गया निर्णय भी **कपूर सिंह बनाम पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और** अन्य 3.एक विकल्प के रूप में, अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने भी इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया है जिसका शीर्षक दर्शन है। सिंह बनाम पंजाब राज्य बिजली निगम लिमिटेड और अन्य 4 से यह तर्क देते हुए कि, किसी भी मामले में, यदि विद्युत अधिनियम के तहत बनाया गया विशेष न्यायालय दीवानी मामले पर निर्णय लेने के लिए सक्षम नहीं है, तो उपभोक्ता अधिनियम की धारा 127 के तहत अपील दायर करके धारा 135 (डी) (ई) के तहत दिए गए आदेश को चुनौती दे सकता है।

(14) इस मामले में शामिल विवाद की सराहना के लिए, भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 की प्रासंगिक धाराओं का संदर्भ होना आवश्यक

है।भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 (संक्षेप में, 'अधिनियम') के प्रासंगिक प्रावधानों को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः-

126. मूल्यांकन।-

1. यदि किसी स्थान या परिसर के निरीक्षण पर या जुड़े हुए या उपयोग किए गए उपकरणों, गैजेट्स, मशीनों, उपकरणों के निरीक्षण के बाद, या किसी व्यक्ति द्वारा रखे गए रिकॉर्ड के निरीक्षण के बाद, मूल्यांकन अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि ऐसा व्यक्ति बिजली के अनधिकृत उपयोग में लिप्त है, तो वह अस्थायी रूप से अपने निर्णय के अनुसार ऐसे व्यक्ति या ऐसे उपयोग से लाभान्वित किसी अन्य व्यक्ति द्वारा देय बिजली शुल्क का आकलन करेगा।

2. अस्थायी निर्धारण का आदेश कब्जे या कब्जे में या स्थान या परिसर के प्रभारी व्यक्ति को उस तरीके से दिया जाएगा जो निर्धारित किया जाए।

3. वह व्यक्ति, जिस पर उप-धारा (2) के तहत आदेश दिया गया है, निर्धारण अधिकारी के समक्ष अनंतिम मूल्यांकन के खिलाफ आपत्तियां, यदि कोई हों, दायर करने का हकदार होगा, जो ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद, ऐसे व्यक्ति द्वारा देय बिजली शुल्क के ऐसे अनंतिम मूल्यांकन के आदेश की सेवा की तारीख से तीस दिनों के भीतर मूल्यांकन का अंतिम आदेश पारित करेगा।

4. अनंतिम मूल्यांकन के आदेश के साथ सेवा करने वाला कोई भी व्यक्ति, इस तरह के मूल्यांकन को प्रतिग्रहण करना कर सकता है और उस पर इस तरह के अनंतिम मूल्यांकन आदेश की सेवा के सात दिनों के भीतर लाइसेंसधारी के साथ निर्धारित राशि जमा कर सकता हैः

5. यदि मूल्यांकन अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि बिजली का अनधिकृत उपयोग हुआ है, तो मूल्यांकन उस पूरी अवधि के लिए किया जाएगा जिसके दौरान बिजली का ऐसा अनधिकृत उपयोग हुआ है और यदि, हालाँकि, जिस अवधि के दौरान बिजली का ऐसा अनधिकृत उपयोग हुआ है, उसका पता नहीं लगाया जा सकता है, तो ऐसी अवधि निरीक्षण की तारीख से तुरंत पहले बारह महीने की अवधि तक सीमित होगी।;

6. इस धारा के तहत निर्धारण उप-धारा (5) में निर्दिष्ट सेवाओं की प्रासंगिक श्रेणी के लिए लागू शुल्क के दोगुने के बराबर दर पर किया जाएगा।

व्याख्याः- इस धारा के प्रयोजनों के लिए, -

(क) "निर्धारण अधिकारी" से राज्य सरकार या बोर्ड या अनुज्ञप्तिधारी, जैसा भी मामला हो, का एक अधिकारी अभिप्रेत है जिसे राज्य सरकार द्वारा नामित किया गया है;

बी।"बिजली के अनधिकृत उपयोग का अर्थ है बिजली का उपयोग -

किसी भी कृत्रिम माध्यम से; या

(ख) किसी ऐसे माध्यम से जो संबंधित व्यक्ति या प्राधिकारी या अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अधिकृत नहीं है; या

iii एक छेड़छाड़ किए गए मीटर द्वारा से; या

(iv) उस उद्देश्य के अलावा जिसके लिए बिजली का उपयोग अधिकृत किया गया था; या

v. उन परिसरों या क्षेत्रों के लिए जिनके लिए बिजली की आपूर्ति अधिकृत थी।

रु. 127.अपीलीय प्राधिकारी से अपील करें।-

1. धारा 126 के तहत किए गए अंतिम आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति, उक्त आदेश के तीस दिनों के भीतर, ऐसे रूप में अपील कर सकता है, जो इस तरह से सत्यापित हो और उसके साथ ऐसा शुल्क हो जो राज्य आयोग द्वारा निर्दिष्ट किया जाए।

2.उप-धारा (1) के तहत निर्धारण के आदेश के खिलाफ किसी भी अपील पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि निर्धारित राशि के * [आधे] के बराबर राशि नकद में या बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से लाइसेंसधारी के साथ जमा नहीं की जाती है और ऐसी जमा राशि का दस्तावेजी साक्ष्य अपील के साथ संलग्न नहीं किया गया है।

3. उप-धारा (1) में निर्दिष्ट अपीलीय प्राधिकारी पक्षों को सुनने के बाद अपील का निपटारा करेगा और उचित आदेश पारित करेगा और आदेश की प्रति निर्धारण अधिकारी और अपीलकर्ता को भेजेगा।

4.उप-धारा (3) के तहत पारित उप-धारा (1) में निर्दिष्ट अपीलीय प्राधिकरण का आदेश अंतिम होगा।

5. पक्षकारसभक सहमतिसँ देल गेल अन्तिम आदेशक विरुद्ध उप-धारा (1) मे निर्दिष्ट अपीलीय प्राधिकारी लग कोनो अपील नहि होयत।

6.जब कोई व्यक्ति निर्धारित राशि का भुगतान करने में चूक करता है, तो वह निर्धारित राशि के अलावा, मूल्यांकन के आदेश की तारीख से तीस दिनों की समाप्ति पर, सोलह प्रतिशत की दर से ब्याज की राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।प्रति वर्ष हर छह महीने में चक्रवृद्धि।

135. बिजली की चोरी।-

1. जो भी, बेईमानी से, -

क. ऊपर, भूमिगत या पानी की लाइनों या केबलों के नीचे, या सेवा तारों, या किसी लाइसेंसधारी या आपूर्तिकर्ता की सेवा सुविधाओं के साथ, जैसा भी मामला हो, नल बनाना, या कोई कनेक्शन बनाना; या

बी. एक मीटर में छेड़छाड़ करता है, एक छेड़छाड़ किए गए मीटर, करंट रिवर्सिंग ट्रांसफॉर्मर, लूप कनेक्शन या किसी अन्य उपकरण या विधि का

उपयोग करता है जो विद्युत प्रवाह के सटीक या उचित पंजीकरण, अंशांकन या मीटरिंग में हस्तक्षेप करता है या अन्यथा इस तरह से परिणाम देता है जिससे बिजली चोरी या बर्बाद हो जाती है; या

ग. बिजली के मीटर, उपकरण, उपकरण या तार को नुकसान पहुंचाता है या नष्ट कर देता है या उनमें से किसी को भी इतना क्षतिग्रस्त या नष्ट होने देता है कि बिजली की उचित या सटीक मीटरिंग में हस्तक्षेप हो; या

घ. छेड़छाड़ किए गए मीटर द्वारा से बिजली का उपयोग करता है; या

ई. बिजली का उपयोग उस उद्देश्य के संक्षिप्त सार अन्य उद्देश्य के लिए करता है जिसके लिए बिजली का उपयोग अधिकृत किया गया था, ताकि बिजली का उपयोग करने या उपभोग करने या उपयोग करने के लिए तीन साल तक की अवधि के कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडनीय होगाः

बशर्ते कि ऐसे मामले में जहां भार अमूर्त, उपभोग, या उपयोग किया गया या निकालना का प्रयास किया गया या उपभोग का प्रयास किया गया या उपयोग करने का प्रयास किया गया -

i. 10 किलोवाट से अधिक नहीं है, पहली सजा पर लगाया गया जुर्माना बिजली की ऐसी चोरी के कारण होने वाले वित्तीय लाभ के तीन गुना से कम नहीं होगा और दूसरी या बाद की सजा की स्थिति में लगाया गया

जुर्माना बिजली की ऐसी चोरी के कारण होने वाले वित्तीय लाभ के छह गुना से कम नहीं होगा।

(ii) 10 किलोवाट से अधिक, पहली सजा पर लगाया गया जुर्माना बिजली की ऐसी चोरी के कारण होने वाले वित्तीय लाभ के तीन गुना से कम नहीं होगा और दूसरी या बाद में दोषी ठहराए जाने की स्थिति में, सजा कम से कम छह महीने के लिए कारावास होगी, लेकिन जो पांच साल तक बढ़ सकती है और बिजली की ऐसी चोरी के कारण होने वाले वित्तीय लाभ के कम से कम छह गुना जुर्माने के साथः

बशर्ते कि किसी व्यक्ति को दूसरे और बाद में दोषी ठहराए जाने की स्थिति में जहां भार 10 किलोवाट से अधिक है, अवशोषित किया गया है, उपभोग किया गया है, या उपयोग किया गया है या निकालना का प्रयास किया गया है या उपभोग का प्रयास किया गया है या उपयोग करने का प्रयास किया गया है, ऐसे व्यक्ति को की कोई भी आपूर्ति प्राप्त करने से भी वंचित किया जाएगा। ऐसी अवधि के लिए बिजली जो तीन महीने से कम नहीं होगी, लेकिन दो साल तक बढ़ सकती है और उस अवधि के लिए किसी अन्य स्रोत या उत्पादन केंद्र से बिजली की आपूर्ति प्राप्त करने से भी प्रतिबंधित होगीः

बशर्ते कि यह भी कि यदि यह साबित हो जाता है कि उपभोक्ता द्वारा बिजली के सार, खपत या उपयोग के लिए कोई निकालना साधन या साधन मौजूद हैं जो बोर्ड या लाइसेंसधारी या आपूर्तिकर्ता द्वारा अधिकृत

नहीं हैं, तो यह तब तक माना जाएगा, जब तक कि इसके विपरीत साबित नहीं हो जाता है कि बिजली का कोई सार, खपत या उपयोग ऐसे उपभोक्ता द्वारा बेईमानी से किया गया है।

1ए. इस अधिनियम के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, लाइसेंसी या आपूर्तिकर्ता, जैसा भी मामला हो, बिजली की ऐसी चोरी का पता चलने पर, तुरंत बिजली की आपूर्ति काट सकता हैः

बशर्ते कि केवल अनुज्ञप्तिधारी या आपूर्तिकर्ता का ऐसा अधिकारी, जो उपयुक्त आयोग द्वारा इस उद्देश्य के लिए अधिकृत किया गया हो या अनुज्ञप्तिधारी या आपूर्तिकर्ता का कोई अन्य अधिकारी, जैसा भी मामला हो, इस प्रकार अधिकृत रैंक से उच्च रैंक का हो, बिजली की आपूर्ति लाइन को काट देगाःबशर्ते कि लाइसेंसी या आपूर्तिकर्ता का ऐसा अधिकारी, जैसा भी मामला हो, ऐसे संबंध विच्छेद के समय से चौबीस घंटे के भीतर अधिकार क्षेत्र वाले पुलिस स्टेशन में ऐसे अपराध के होने के संबंध में लिखित रूप में शिकायत दर्ज करेगाः

परन्तु यह भी कि अनुज्ञप्तिधारी या आपूर्तिकर्ता, जैसा भी मामला हो, इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित राशि या बिजली शुल्क जमा करने या भुगतान करने पर, इस धारा के दूसरे परंतुक में निर्दिष्ट शिकायत दर्ज करने के दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे जमा या भुगतान के अड़तालीस घंटे के भीतर बिजली की आपूर्ति लाइन को बहाल करेगा।

2. राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत, अनुज्ञप्तिधारी या आपूर्तिकर्ता का कोई भी अधिकारी, जैसा भी मामला हो निरीक्षण करें, तोड़ें और किसी भी स्थान या परिसर की तलाशी लें जिसमें उसे यह विश्वास करने का कारण है कि बिजली का अनधिकृत रूप से उपयोग किया गया है या किया जा रहा है;

ख. ऐसे सभी उपकरणों, उपकरणों, तारों और किसी अन्य सुविधा प्रदाता या वस्तु की खोज, जब्त और उसे हटा दें जिसका उपयोग बिजली के अनधिकृत उपयोग के लिए किया गया है या किया जा रहा है।

ग. उप-धारा (1) के तहत अपराध के संबंध में किसी भी कार्यवाही के लिए उपयोगी या प्रासंगिक होने वाली किसी भी लेखा पुस्तक या दस्तावेजों की जांच या जब्त करना और उस व्यक्ति को, जिसकी अभिरक्षा से ऐसी लेखा पुस्तकें या दस्तावेज जब्त किए गए हैं, उनकी प्रतियां बनाने या उनकी उपस्थिति में उनसे उद्धरण लेने की अनुमति देना।

3. तलाशी स्थल पर रहने वाला या उसकी ओर से कोई भी व्यक्ति तलाशी के दौरान मौजूद रहेगा और ऐसी तलाशी के दौरान जब्त की गई सभी चीजों की एक सूची तैयार की जाएगी और ऐसे रहने वाले या व्यक्ति को दी जाएगी जो सूची पर हस्ताक्षर करेगाः

बशर्ते कि सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच किसी भी घरेलू स्थानों या घरेलू परिसर का कोई निरीक्षण, तलाशी और जब्ती नहीं की जाएगी, सिवाय ऐसे परिसर में रहने वाले किसी वयस्क पुरुष सदस्य की उपस्थिति के।

4. तलाशी और जब्ती से संबंधित दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के प्रावधान इस अधिनियम के तहत तलाशी और जब्ती पर, जहां तक हो सके, लागू होंगे।

धारा 143।(निर्णय लेने की शक्ति):--- (1) इस उद्देश्य के लिए इस अधिनियम के तहत निर्णय लेने के लिए, उपयुक्त आयोग किसी भी संबंधित व्यक्ति को कोई जुर्माना लगाने के उद्देश्य से सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद, उचित सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से जांच करने के लिए अपने किसी भी सदस्य को एक न्यायनिर्णायक अधिकारी के रूप में नियुक्त करेगा।(2) जाँच करते समय, न्यायनिर्णायक अधिकारी को समन भेजने और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित किसी भी व्यक्ति की उपस्थिति को साक्ष्य देने या कोई दस्तावेज पेश करने के लिए लागू करने की शक्ति होगी जो न्यायनिर्णायक अधिकारी की राय में जाँच के विषय के लिए उपयोगी या प्रासंगिक हो सकता है, और यदि ऐसी जाँच पर, वह संतुष्ट है कि व्यक्ति धारा 29 या धारा 33 या धारा 43 के प्रावधानों का पालन करने में विफल रहा है, तो वह ऐसा जुर्माना लगा सकता है जो वह उन धाराओं में से किसी के प्रावधानों के अनुसार उचित समझता है।

145. दीवानी अदालत का अधिकार क्षेत्र नहीं होना चाहिए।

1. मुकदमा 126 में निर्दिष्ट किसी निर्धारण अधिकारी या मुकदमा 127 में निर्दिष्ट किसी अपीलीय प्राधिकारी या इस अधिनियम के तहत नियुक्त न्यायनिर्णायक अधिकारी को इस अधिनियम द्वारा या उसके तहत निर्धारित करने का अधिकार है और इस अधिनियम द्वारा या उसके तहत प्रदत्त किसी शक्ति के अनुसरण में की गई या की जाने वाली किसी कार्रवाई के संबंध में किसी भी अदालत या अन्य अधिकार क्षेत्र द्वारा कोई निषेधाज्ञा नहीं दी जाएगी।

धारा 153।(विशेष न्यायालयों का गठन):--- (1) द. राज्य सरकार, 1 [धारा 135 से 140 और धारा 150] में निर्दिष्ट अपराधों की त्वरित सुनवाई प्रदान करने के उद्देश्यों के लिए, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों के लिए जितने आवश्यक हों उतने विशेष अदालत का गठन कर सकती है, जो अधिसूचना में निर्दिष्ट किए जाएं।(2) एक विशेष न्यायालय में एक एकल न्यायाधीश होगा जिसकी नियुक्ति उच्च न्यायालय की सहमति से राज्य सरकार द्वारा की जाएगी।(3) कोई व्यक्ति विशेष न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक योग्य नहीं होगा जब तक कि वह ऐसी नियुक्ति से ठीक पहले एक अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश न हो।(4) जहाँ किसी विशेष न्यायालय के न्यायाधीश का पद रिक्त है, या ऐसा न्यायाधीश ऐसे विशेष न्यायालय की बैठक के सामान्य स्थान से अनुपस्थिति है, या वह अपने

कर्तव्यों के पालन के लिए बीमारी या अन्यथा अक्षम है, वहाँ विशेष न्यायालय में किसी भी तत्काल कार्य का निपटारा किया जाएगा-(क) विशेष न्यायालय में अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने वाले न्यायाधीश द्वारा, यदि कोई हो; (ख) जहाँ ऐसा कोई अन्य न्यायाधीश उपलब्ध नहीं है, विशेष न्यायालय की बैठक के सामान्य स्थान पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले जिला और सत्र न्यायाधीश के निर्देश के अनुसार, जैसा कि उप-धारा (1) के तहत अधिसूचित किया गया है।

154. विशेष न्यायालय की प्रक्रिया और शक्ति।-

1. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में कुछ भी निहित होने के बावजूद, धारा 135 से 140 और धारा 150 के तहत दंडनीय प्रत्येक अपराध केवल उस विशेष न्यायालय द्वारा विचारण योग्य होगा जिसके अधिकार क्षेत्र में ऐसा अपराध किया गया है।

2. जहाँ किसी न्यायालय को किसी जांच या विचारण के दौरान यह प्रतीत होता है कि धारा 135 से 140 462 के तहत दंडनीय अपराध है और धारा 150 किसी ऐसे अपराध के संबंध में कि मामला वह है जो इस अधिनियम के तहत गठित विशेष न्यायालय द्वारा उस क्षेत्र के लिए विचारण योग्य है जिसमें ऐसा मामला उत्पन्न हुआ है, वह ऐसे मामले को ऐसे विशेष न्यायालय को हस्तांतरित करेगा और उसके बाद ऐसे मामले की सुनवाई और निपटान इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ऐसे विशेष न्यायालय द्वारा किया जाएगाः

बशर्ते कि ऐसे विशेष न्यायालय के लिए किसी विशेष न्यायालय में मामले के हस्तांतरण से पहले अभियुक्त की उपस्थिति के मामले में किसी भी न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए साक्ष्य, यदि कोई हो, पर कार्रवाई करना विधिसम्मत होगाः

बशर्ते कि यदि ऐसे विशेष न्यायाधीशालय की राय है कि न्यायाधीश के हित में किसी भी गवाह की आगे की जांच, प्रतिपरीक्षा और पुनःपरीक्षा की आवश्यकता है, जिसका साक्ष्य पहले ही दर्ज किया जा चुका है, तो वह ऐसे किसी भी गवाह को फिर से तलब कर सकता है और ऐसी आगे की जांच के बाद, प्रतिपरीक्षा या पुनःपरीक्षा, यदि कोई हो, जो वह अनुमति दे, गवाह को आरोपमुक्त कर देगा।

3. विशेष न्यायालय, धारा 260 की उप-धारा (1) या दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 262 में किसी बात के होते हुए भी, धारा 135 से 140 और धारा 150 में निर्दिष्ट अपराध पर उक्त संहिता में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संक्षिप्त तरीके से मुकदमा चला सकता है और उक्त संहिता की धारा 263 से 265 के प्रावधान, जहां तक हो सके, ऐसे मुकदमे पर लागू होंगेःबशर्ते कि जहां इस उप-धारा के तहत संक्षिप्त मुकदमे के दौरान, विशेष न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि मामले की प्रकृति ऐसी है कि ऐसे मामले का संक्षिप्त तरीके से परीक्षण करना अवांछनीय है, विशेष न्यायालय किसी भी गवाह को वापस बुलाएगा जिसकी जांच की गई हो और ऐसे अपराध के मुकदमे के लिए उक्त

संहिता के प्रावधानों द्वारा प्रदान की गई तरीके से मामले की फिर से सुनवाई करने के लिए आगे बढ़ेगाः

बशर्ते कि इस धारा के तहत संक्षिप्त मुकदमे में किसी भी दोषसिद्धि के मामले में, एक विशेष न्यायालय के लिए पांच साल से अधिक की अवधि के लिए कारावास की सजा पारित करना विधिसम्मत होगा।

4. एक विशेष न्यायालय, किसी ऐसे व्यक्ति का साक्ष्य प्राप्त करने की दृष्टि से, जिसके बारे में माना जाता है कि वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित या उससे गुप्त रहा है, ऐसे व्यक्ति को पूर्ण और बनाने की शर्त पर क्षमा कर सकता है। अपराध से संबंधित उसकी जानकारी में आने वाली परिस्थितियों का वास्तविक प्रकटीकरण और संबंधित प्रत्येक अन्य व्यक्ति को, चाहे वह अपराध करने में प्रमुख या दुष्प्रेरक के रूप में हो, और इस तरह से दी गई कोई भी माफी, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 308 के प्रयोजनों के लिए, इसकी धारा 307 के तहत दी गई मानी जाएगी।

5. विशेष न्यायालय किसी उपभोक्ता या व्यक्ति के विरुद्ध ऊर्जा की चोरी के लिए धन के संदर्भ में नागरिक दायित्व का निर्धारण करेगा जो ऊर्जा की चोरी या चोरी की सटीक अवधि का पता चलने की तारीख से पहले बारह महीने की अवधि के लिए लागू शुल्क दर के दो गुना के बराबर राशि से कम नहीं होगी, यदि यह निर्धारित किया जाता है कि जो भी

कम हो और इस तरह निर्धारित नागरिक दायित्व की राशि की वसूली इस तरह की जाएगी जैसे कि यह नागरिक न्यायालय की डिक्री हो।

6. यदि विशेष न्यायालय द्वारा अंत में इस प्रकार निर्धारित नागरिक दायित्व उपभोक्ता या व्यक्ति द्वारा जमा की गई राशि से कम है, तो उपभोक्ता या व्यक्ति द्वारा बोर्ड या लाइसेंसधारी या संबंधित व्यक्ति को, जैसा भी मामला हो, जमा की गई अतिरिक्त राशि, बोर्ड या लाइसेंसधारी या संबंधित व्यक्ति द्वारा, विशेष न्यायालय के आदेश के संचार की तारीख से एक पखवाड़े के भीतर, भारतीय रिजर्व बैंक की प्रचलित प्रमुख ऋण दर पर ब्याज के साथ, ऐसी जमा की तारीख से भुगतान की तारीख तक की अवधि के लिए वापस कर दी जाएगी।

व्याख्याः इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "नागरिक दायित्व" का अर्थ है बोर्ड या लाइसेंसधारी या संबंधित व्यक्ति द्वारा, जैसा भी मामला हो, धारा 135 से 140 और धारा 150 में निर्दिष्ट अपराध के कारण हुई हानि या क्षति।

(15) अधिनियम की धारा 126,127 और 135 के अवलोकन से पता चलता है कि अधिनियम की धारा 126 और 127 बिजली के अनधिकृत उपयोग से संबंधित है और बिजली के अनधिकृत उपयोग के मामले में मूल्यांकन आदेश पारित करने के लिए एक पूर्ण अदालत का गठन करती है।इसके विपरीत, अधिनियम की धारा 135 बिजली की चोरी से संबंधित मामलों से संबंधित है। ये दोनों अधिनियम के विभिन्न अध्यायों में निहित

अलग-अलग मामले हैं। इस संबंध में स्थिति पहले ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा द एग्जीक्यूटिव 464 में रिपोर्ट की गई है।

इंजीनियर और एक अन्य बनाम मेसर्स श्री सीताराम राइस मिल 5 जो है

यहाँ नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः-

15. उनके स्पष्ट रूप से पढ़ने पर, 2003 के अधिनियम की धारा 126 और 135 की सामग्री में स्पष्ट अंतर स्पष्ट हैं।वे अलग-अलग और अलग-अलग प्रावधान हैं जो अलग-अलग क्षेत्रों में काम करते हैं और जिनका कानून में कोई सामान्य आधार नहीं है।हम पहले ही देख चुके हैं कि 2003 के अधिनियम की धारा 126 और 127 को एक साथ पढ़कर एक पूर्ण संहिता का गठन किया गया है, जिसमें उन मामलों में मूल्यांकन के आदेश को पारित करने के लिए सभी प्रासंगिक विचार शामिल हैं जो 2003 के अधिनियम की धारा 135 के तहत नहीं आते हैं। 2003 के अधिनियम की धारा 135 'अपराध और दंड' की धारा 'बिजली की चोरी' से संबंधित भाग XIV के तहत आती है।धारा 'जो कोई भी, बेईमानी से' 2003 के अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (1) के धारा (ए) से (ई) के तहत निर्दिष्ट किसी भी या सभी कार्यों को करता है ताकि बिजली का संक्षिप्त सार या उपभोग या उपयोग किया जा सके, वह तीन साल तक की अवधि के कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडनीय होगा।इन प्रावधानों या उसके प्रावधान के तहत निर्दिष्ट दंड के अधिरोपण के अलावा, 2003 के अधिनियम की

धारा 135 की उप-धारा (1ए) में प्रावधान है कि 2003 के अधिनियम के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अनुज्ञप्तिधारी या आपूर्तिकर्ता, जैसा भी मामला हो, उपयुक्त आयोग द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत रैंक के अधिकारी द्वारा से, तुरंत बिजली की आपूर्ति काट सकता है और यहां तक कि उक्त धारा की उप-धारा (2) से (4) के तहत गणना किए गए अन्य उपाय भी कर सकता है।2003 के अधिनियम की धारा 135 के तहत लगाया जा सकने वाला जुर्माना सीधे तौर पर दोषसिद्धि की संख्या के आनुपातिक है और यह भार की सीमा पर भी निर्भर करता है।इन प्रावधानों के विपरीत, 2003 के अधिनियम की धारा 126 उन मामलों में लागू होगी जहां बिजली की कोई चोरी नहीं होती है, लेकिन बिजली की खपत आपूर्ति के नियमों और शर्तों का उल्लंघन करके की जा रही है, जिससे कदाचार हो रहा है जो 'बिजली का अनधिकृत उपयोग' अभिव्यक्ति के अंतर्गत आ सकता है।यह मूल्यांकन/कार्यवाही एक मूल्यांकन अधिकारी द्वारा परिसर के निरीक्षण और इस निष्कर्ष की रिकॉर्डिंग के साथ शुरू होगी कि ऐसा उपभोक्ता 'बिजली के अधिकृत उपयोग' में लिप्त है।फिर आकलन अधिकारी अपने सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार, ऐसे उपभोक्ता द्वारा देय बिजली शुल्क का अस्थायी रूप से आकलन करेगा, साथ ही 2003 के अधिनियम की धारा 126 (2) के संदर्भ में एक अस्थायी मूल्यांकन आदेश पारित करेगा। अधिकारी 2003 के अधिनियम की धारा 126 (3) के संदर्भ में किसी भी ऐसे उपभोक्ता को अस्थायी मूल्यांकन के

खिलाफ अपनी आपत्तियां, यदि कोई हों, दायर करने के लिए बाध्य करने के लिए भी बाध्य है, इससे पहले कि अस्थायी मूल्यांकन के ऐसे आदेश की सेवा की तारीख से तीस दिनों के भीतर मूल्यांकन का अंतिम आदेश पारित किया जाए।इसके बाद, अनंतिम मूल्यांकन के आदेश के साथ सेवा करने वाला कोई भी व्यक्ति इस तरह के मूल्यांकन को प्रतिग्रहण करना कर सकता है और उस पर इस तरह के अनंतिम मूल्यांकन आदेश की सेवा के सात दिनों के भीतर राशि जमा कर सकता है या 2003 के अधिनियम की धारा 127 के तहत परिणामी अंतिम आदेश के खिलाफ अपील कर सकता है। धारा 126 के तहत निर्धारण का आदेश और जिस अवधि के लिए ऐसा आदेश पारित किया जाएगा, वह 2003 के अधिनियम की धारा 126 की उप-धारा (5) और (6) के संदर्भ में होना चाहिए। धारा 126 का स्पष्टीकरण कुछ महत्व का है, जिस पर हम जल्द ही चर्चा करेंगे।2003 के अधिनियम की धारा 126 अध्याय 12 के तहत आती है और जांच और प्रवर्तन से संबंधित है और मूल्यांकन अधिकारी को मूल्यांकन का आदेश पारित करने का अधिकार देती है।

16. 2003 के अधिनियम की धारा 135 बिजली की चोरी के अपराध और ऐसी चोरी के लिए लगाए जा सकने वाले जुर्माने से संबंधित है।यह पूरी तरह से आपराधिक न्यायशास्त्र के आयामों के भीतर आता है और चोरी के मामले को खोजने के लिए प्रासंगिक कारकों में से एक है।इसके

विपरीत, 2003 के अधिनियम की धारा 126 किसी भी आपराधिक इरादे की बात नहीं करती है और मुख्य रूप से नागरिक कानून के तहत उपलब्ध एक कार्रवाई और उपाय है।इसमें ऐसी कोई विशेषताएँ या तत्व नहीं हैं जो मेन्स रिया की आपराधिक अवधारणा से जुड़े हों।

17.इस प्रकार, यह स्पष्ट होगा कि 2003 के अधिनियम की धारा 126 के तहत 'बिजली का अनधिकृत उपयोग' अभिव्यक्ति अनधिकृत उपयोग के मामलों से संबंधित है, भले ही इरादे की अनुपस्थिति में में भी।ये मामले निश्चित रूप से उन मामलों से अलग होंगे जहां 2003 के अधिनियम की धारा 135 के तहत सूचीबद्ध किसी भी तरीके से बिजली का बेईमान निकालना होता है। एक स्पष्ट उदाहरण होगा, जहां एक उपभोक्ता ने स्थापित भार सरलीकरण की तुलना में अत्यधिक भार का उपयोग किया है और आपूर्ति के नियमों और शर्तों का उल्लंघन किया है, तो मामला 2003 के अधिनियम की धारा 126 के तहत आएगा। दूसरी ओर, जहां एक उपभोक्ता ने 2003 के अधिनियम की धारा 135 (ए) से 135 (ई) के तहत निर्दिष्ट किसी भी साधन और तरीके से बेईमानी के इरादे से और प्राधिकरण के बिना ऊर्जा का अपव्यय किया है, जैसे कि स्थापित मीटर को दरकिनार करते हुए सीधे कनेक्शन का प्रावधान करना।इसलिए, एक ओर 2003 के अधिनियम की धारा 126 और दूसरी ओर 2003 के अधिनियम की धारा 135 के तहत आने वाले मामलों के बीच स्पष्ट अंतर है।कानून में उनके बीच कोई समानता नहीं है।वे

विभिन्न और अलग-अलग क्षेत्रों में काम करते हैं।आकलन अधिकारी को बिजली के अनधिकृत उपयोग के मामलों में मूल्यांकन का अस्थायी और अंतिम आदेश पारित करने की शक्तियां दी गई हैं और अनुबंधित भार से अधिक बिजली की खपत के मामले पूरी तरह से इस तरह के अधिकार के अंतर्गत आएंगे।विधायी इरादा कदाचार और बिजली के अनधिकृत उपयोग और फिर चोरी के मामलों को शामिल करना है जो 2003 के अधिनियम की धारा 135 के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित है।

18. 2003 के अधिनियम की संक्षिप्त सार 135 में महत्वपूर्ण रूप से इन शब्दों का उपयोग किया गया है कि 'जो कोई भी, बेईमानी से' बिजली का उपयोग करने या उसका उपभोग करने के लिए सूचीबद्ध कार्यों में से कोई भी करता है, उसे 2003 के अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार दंडित किया जाएगा। 'बेईमानी' एक मानसिक स्थिति है जिसका अस्तित्व किसी व्यक्ति को उस संक्षिप्त सार के प्रावधानों के तहत दंडित करने से पहले दिखाया जाना चाहिए।

(16) माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा बताए गए उपरोक्त प्रस्तावों के आलोक में, यह स्पष्ट है कि बिजली का अनधिकृत उपयोग पूरी तरह से एक अलग मामला है और इससे मूल्यांकन अधिकारी को निपटना होगा।यह आकलन उपभोक्ता से ली जाने वाली राशि के बारे में मूल्यांकन अधिकारियों द्वारा किया जाना है।निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित ऐसा आदेश अपील योग्य आदेश है।इसलिए उपभोक्ता अधिनियम और उसके

तहत बनाए गए नियमों के तहत उपलब्ध उपायों में इस तरह के मूल्यांकन पर सवाल उठा सकता है।दूसरी ओर, अधिनियम की धारा 135 चोरी को परिभाषित करती है।चोरी के लिए उपभोक्ता पर बिजली की चोरी के अपराध के लिए मुकदमा चलाया जाना आवश्यक है।विभाग से चोरी का मामला बनाने और पुलिस को रिपोर्ट करने या शिकायतकर्ता के रूप में आपराधिक अधिकार क्षेत्र की सक्षम अदालत में भेजने की आवश्यकता होती है।यह आपराधिक अधिकार क्षेत्र की सक्षम अदालत को देखना है कि क्या ऐसे व्यक्ति ने बिजली की चोरी की है या नहीं।अब तक उल्लिखित प्रक्रिया में कोई जटिलता नहीं है।हालांकि समस्या तब उत्पन्न होती है जब विभाग के अधिकारी आपराधिक अभियोजन के द्वारा प्राथमिकी दर्ज करते हैं और उपभोक्ता के दायित्व के कथित मूल्यांकन का आदेश भी पारित करते हैं और ऐसे उपभोक्ता को मांग नोटिस देते हैं; उसे उस राशि को चोरी और/या जुर्माने के रूप में उसके द्वारा खपत की गई बिजली के कारण जमा करने के द्वारा कहते हैं। इस स्थिति में, सवाल यह है कि क्या मूल्यांकन अधिकारी के पास कथित चोरी और/या उसके लिए जुर्माने द्वारा से खपत की गई बिजली के लिए उपभोक्ता के दायित्व को तय करने का कोई अधिकार है।और यदि नहीं तो क्या उपभोक्ता को अधिनियम की धारा 145 के प्रावधान के अनुसार दीवानी अदालत के अधिकार क्षेत्र से वंचित करके उसे बिना किसी उपाय के छोड़ा जा सकता है। दूसरा पहलू यह है कि क्या किसी उपभोक्ता को अधिनियम की धारा 127 के तहत प्रदान किए गए उपाय का लाभ उठाने के लिए कहा जा

सकता है; उन मामलों में भी जहां विभाग बिजली की चोरी का आरोप लगाता है न कि अधिनियम की धारा 126 द्वारा निर्धारित बिजली के अनधिकृत उपयोग का।

(17) अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने बताया है कि अधिनियम की धारा 154 में बिजली की चोरी के मामलों से निपटने के लिए विशेष अदालत का प्रावधान किया गया है।उनका तर्क है कि चूंकि अधिनियम की धारा 154 (5) उपभोक्ता के खिलाफ 'नागरिक दायित्व' का निर्धारण करने का भी प्रावधान करती है, इसलिए दीवानी अदालत का अधिकार क्षेत्र वर्जित है और अधिनियम की धारा 153 और 154 द्वारा गठित विशेष न्यायालय पक्षों के बीच दीवानी मुद्दों को निर्धारित करने के लिए एकमात्र सक्षम प्राधिकारी होगा।अपने तर्क का समर्थन करने के लिए उन्होंने इस न्यायालय द्वारा दिए गए ऊपर उल्लिखित निर्णयों पर भरोसा किया है।

(18) हालाँकि, यह न्यायालय अपीलार्थियों के लिए विद्वान अधिवक्ता के प्रस्तुत करने के साथ खुद को सहमत नहीं पाता है।निम्नलिखित पैराग्राफ में उल्लिखित कारणों के लिए, मैं अपनी बहन और भाई न्यायाधीशों से सहमत होने में विफल रहता हूं और उपरोक्त मामलों में यह मानते हुए असहमत हूं कि दीवानी अदालत की अधिकार क्षेत्र अधिनियम की धारा 145 और 154 के प्रावधानों से बाहर है।

(19) पानीपत और अन्य (उपर्युक्त) के निर्णय के अवलोकन से पता चलता है कि अधिनियम की धारा 126,127 और 135 और अन्य संबंधित

धाराओं के संबंधित दायरे के बारे में आत्यन्तिक रूप कोई चर्चा नहीं हुई है। अधिनियम की धारा 145 की खुली भाषा के आधार पर, दीवानी अदालत के अधिकार क्षेत्र को वर्जित माना गया है।इसलिए इस निर्णय ने अधिनियम की संबंधित लागू धाराओं पर विचार नहीं किया है और निर्णय नहीं लिया है। इसलिए, यह एक मिसाल के रूप में अपीलार्थियों के लिए कोई मददगार नहीं है।मेसर्स भारत ऑटो केयर (उपरोक्त) के मामले में, न्यायालय ने अधिनियम के प्रावधानों का उल्लेख किया और अधिनियम की धारा 145 के दायरे पर विचार करते हुए, न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले पर इस प्रभाव से भरोसा किया कि हालांकि कोई विशिष्ट 468 नहीं है अधिनियम की धारा 145 में किसी भी मामले के संबंध में किसी भी कार्यवाही पर विचार करने के लिए दीवानी अदालत की अधिकारिता को हटाने का प्रावधान है, जिसे विशेष अदालत को अधिनियम द्वारा निर्धारित करने का अधिकार दिया गया है, हालांकि, दिल्ली उच्च न्यायालय के विचार में; चोरी के मामलों में दीवानी दायित्व के बारे में निर्णय, निहित रूप से, दीवानी अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर था; अधिनियम की धारा 153 और 154 के प्रावधान को देखते हुए, जहां एक विशेष अदालत को 'दीवानी दायित्व' निर्धारित करने के लिए अधिकार क्षेत्र दिया गया है।

(20) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि आक्षेपित आदेश अधिनियम की धारा 126 के तहत प्रक्रिया का पालन

करते हुए निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित किए गए थे और इसलिए, दीवानी अदालत के पास अभियोक्ता द्वारा अधिनियम की धारा 127 के तहत प्रदान किए गए सभी उपायों को समाप्त करने से पहले कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा। इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि अधिनियम की धारा 154 (5) के प्रावधानों को देखते हुए दीवानी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बाधित किया जाएगा। निर्णय में दिए गए तर्क पारस्परिक रूप से विनाशकारी हैं और एक दूसरे के विपरीत हैं।

(21) कपूर सिंह के मामले (ऊपर) के अगले फैसले में अदालत ने कहा है कि इस बिजली अधिनियम के तहत गठित विशेष अदालत की दोहरी जिम्मेदारी है कि वह चोरी और नागरिक दायित्व दोनों कोणों से मामले की जांच करे और तदनुसार आदेश पारित करे।वास्तव में, इस मामले में न्यायालय की निर्भरता इस तथ्य पर भी थी कि बिजली की चोरी से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय का गठन किया गया था और इसलिए, दीवानी न्यायालय की अधिकार क्षेत्र को बाहर रखा गया है।हालाँकि, यह निर्णय इस मुद्दे से संबंधित नहीं है कि क्या मूल्यांकन अधिकारी कथित चोरी के मामले में भी उपभोक्ता के खिलाफ दायित्व का आदेश पारित कर सकता है और यदि ऐसा आदेश पारित किया जाता है, तो प्रभावित उपभोक्ता द्वारा उस आदेश पर सवाल कैसे उठाया जा सकता है।

(22) अंत में, दर्शन सिंह के मामले (ऊपर) के फैसले में अदालत ने थोड़ा अलग दृष्टिकोण अपनाया और कहा कि हालांकि अधिनियम की धारा 154 उपभोक्ता को चोरी के कारण वसूली के लिए विभागीय अधिकारियों द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने में सक्षम बनाने के लिए किसी भी स्थिति से सख्ती से नहीं निपटती है, जबकि अधिनियम की धारा 145 दीवानी अदालत के अधिकार क्षेत्र को प्रतिबंधित करती है।यह देखते हुए कि उपभोक्ता को उपचार से वंचित नहीं छोड़ा जा सकता है, अदालत ने कहा कि अधिनियम की धारा 135 के तहत बिजली की चोरी के मामलों में भी उपभोक्ता अधिनियम की धारा 127 के तहत अपील दायर कर सकता है और ऐसी अपील अधिकार क्षेत्र के बिना नहीं होगी।हालाँकि इस मामले में दीवानी अदालत के अधिकार क्षेत्र के बहिष्करण के सवाल पर अदालत द्वारा सख्ती से निर्णय नहीं लिया गया था।इसके अलावा, इस मामले में दी गई व्याख्या के खिलाफ भी है। अधिनियम की धारा 154 का प्रावधान; जो विशेष न्यायालय को 'नागरिक दायित्व' तय करने की शक्ति देता है।

(23) सिविल प्रक्रिया संहिता (संक्षेप में, 'सी. पी. सी.') सिविल न्यायालय को कानून के कुछ अन्य वैधानिक प्रावधानों के तहत विशेष रूप से वर्जित को छोड़कर नागरिक प्रकृति के सभी प्रकार के मुकदमों की सुनवाई करने के लिए योजना शक्ति और अधिकार क्षेत्र प्रदान करती है।धारा 9 में निहित सी. पी. सी. के प्रासंगिक प्रावधान को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः-

9. अदालतें सभी दीवानी मुकदमों की सुनवाई तब तक करें जब तक कि वे प्रतिबंधित न हों।- अदालतें

(इसमें निहित प्रावधानों के अधीन) के पास उन मुकदमों को छोड़कर नागरिक प्रकृति के सभी मुकदमों का परीक्षण करने की अधिकार क्षेत्र होगी, जिनमें उनका संज्ञान या तो स्पष्ट रूप से या निहित रूप से वर्जित है।

स्पष्टीकरण 1.–जिस मुकदमे में संपत्ति या पद के अधिकार का विरोध किया जाता है, वह नागरिक प्रकृति का मुकदमा है, इसके बावजूद कि ऐसा अधिकार पूरी तरह से धार्मिक संस्कारों या समारोहों के बारे में प्रश्नों के निर्णय पर निर्भर हो सकता है।स्पष्टीकरण ।-इस धारा के प्रयोजनों के लिए, यह मायने नहीं रखता कि स्पष्टीकरण । में निर्दिष्ट कार्यालय से कोई शुल्क संलग्न है या नहीं या ऐसा कार्यालय किसी विशेष स्थान से संलग्न है या नहीं।

(24) इस प्रावधान के एक नंगे अवलोकन से पता चलता है कि दीवानी अदालत के पास संपत्ति, कार्यालय या यहां तक कि अन्य मामलों से संबंधित सभी विवादों का मुकदमा चलाने का अधिकार क्षेत्र है जो नागरिक के नागरिक अधिकारों को प्रभावित करते हैं।दीवानी अदालत के अधिकार क्षेत्र को केवल वैधानिक कानून का एक और प्रावधान करके रोका जा सकता है जो स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ से दीवानी अदालतों के अधिकार क्षेत्र को छीन लेता है।

(25) हालाँकि, आगे बढ़ने से पहले यह याद दिलाना आवश्यक है कि दीवानी न्यायालय की अधिकार क्षेत्र के बहिष्करण के प्रश्न पर विचार करते समय यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि अनुमान दीवानी न्यायालय की अधिकार क्षेत्र के अस्तित्व के पक्ष में होगा; जहाँ तक दीवानी मामलों का संबंध है।दूसरा, दीवानी अदालत की अधिकार क्षेत्र को छोड़कर किसी प्रावधान की व्याख्या करते समय; ऐसे प्रावधान की प्रतिबंधात्मक व्याख्या की जानी चाहिए ताकि नागरिकों के नागरिक अधिकारों के निर्धारण में दीवानी अदालत की अधिकार क्षेत्र को बनाए रखा जा सके।इसलिए, न्यायालयों से उस प्रावधान में उन शब्दों और वाक्यांशों को शामिल करने की अपेक्षा नहीं की जाती है जो कथित रूप से दीवानी न्यायालय की अधिकार क्षेत्र को बाहर करते हैं।प्रावधान को जैसा है वैसा ही पढ़ना होगा और अधिनियम को समग्र रूप से पढ़ते समय इसका शाब्दिक अर्थ दिया जाना चाहिए।अंत में, यदि सिविल न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को विशेष रूप से में बाहर रखा गया है। मामला, नाम से, तो दीवानी न्यायालय की अधिकार क्षेत्र को छोड़कर ऐसे प्रावधान को प्रधानता दी जानी चाहिए।

(26) उपरोक्त सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, यदि कोई अधिनियम की धारा 145 के प्रावधान का विश्लेषण करता है, तो यह स्पष्ट है कि सिविल न्यायालय की अधिकारिता को उन मामलों के संबंध में वर्जित कर दिया गया है जिनके संबंध में 'निर्धारण अधिकारी' के पास अधिनियम की धारा

126 के तहत अधिकार क्षेत्र है या 'अपीलीय प्राधिकरण' के पास अधिनियम की धारा 127 के तहत अपील पर निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र है। इसके अलावा, इस प्रावधान में उन मामलों की अधिकारिता को शामिल नहीं किया गया है जिनके बारे में इस अधिनियम के तहत नियुक्त 'न्यायनिर्णायक अधिकारी' को निर्धारित करने का अधिकार है।अधिनियम की धारा 143 न्यायनिर्णायक अधिकारियों के निर्धारण के लिए आरक्षित मामलों से निपटने के लिए उपयुक्त आयोग द्वारा नियुक्त न्यायनिर्णायक अधिकारी की शक्तियों को परिभाषित करती है।इसलिए, यह स्पष्ट है कि जहां तक अधिनियम की धारा 145 की खुली भाषा का संबंध है, यह केवल उन मामलों में दीवानी अदालत के अधिकार क्षेत्र को प्रतिबंधित करता है जहां निर्धारण अधिकारी को अधिनियम की धारा 126 के तहत आकलन करने की शक्ति है, अपीलीय प्राधिकरण को अधिनियम की धारा 127 के तहत अपील सुनने की शक्ति है या न्यायनिर्णायक अधिकारी को अधिनियम की धारा 143 के तहत निर्णय लेने की शक्ति है। ऐसा कोई चौथा पहलू नहीं है जिसके बारे में दीवानी अदालत की अधिकारिता अधिनियम के प्रावधान द्वारा स्पष्ट रूप से वर्जित है। अधिनियम की धारा 145 में यह निर्धारित नहीं किया गया है कि सिविल न्यायालय की अधिकारिता को उन मामलों के संबंध में बाहर रखा जाएगा जिनके बारे में अधिनियम की धारा 153 और 154 के तहत गठित विशेष न्यायालय को निर्णय लेने का अधिकार है।इसलिए, किसी भी मामले के संबंध में, जिसे इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत गठित विशेष

अदालत को तय करना है; दीवानी अदालत की अधिकार क्षेत्र अधिनियम की धारा 145 के प्रावधानों द्वारा 'स्पष्ट रूप से' वर्जित नहीं है। अतः केवल यह तथ्य कि अधिनियम की धारा 153 और 154 के तहत विशेष अदालत का गठन किया गया है, अपने आप में दीवानी न्यायालय की अधिकार क्षेत्र के बहिष्करण का आधार नहीं है।

(27) मामले का अगला पहलू यह है कि क्या किसी आवश्यक 'निहितार्थ' से; विशेष न्यायालय के लिए प्रावधान और उन्हें प्रदान की गई शक्तियां, या विशेष न्यायालय द्वारा लिए गए निर्णय से दीवानी न्यायालय की अधिकार क्षेत्र समाप्त हो जाती है?

(28) अधिनियम में निहित प्रावधानों के एक नंगे अवलोकन से पता चलता है कि चोरी के आरोपों के मामले में, अधिकारी, लाइसेंसधारी या आपूर्तिकर्ता द्वारा पुलिस या अदालत को चोरी की सूचना देना, चोरी के अपराध का चक्रवृद्धि और उपभोक्ता द्वारा अपराध का गैर-चक्रवृद्धि/प्रतिस्पर्धा के मामले में, चोरी के अपराध का निर्धारण और दंड इसलिए, पूरी तरह से एक अलग भाग में निहित है और अधिनियम का अध्याय; जो केवल अपराध और दंड से संबंधित है।हालांकि कुछ कारक; जैसा कि अधिनियम की धारा 126 में उल्लेख किया गया है; अनधिकृत उपयोग को परिभाषित करना, और चोरी को परिभाषित करने वाले अधिनियम की धारा 135 अति-विलंबित हैं, हालांकि, अधिनियम की धारा 135 के तहत परिभाषित चोरी के आरोप के लिए पुरुष कारण का तत्व

एक आवश्यक शर्त है। और यदि पुरुष अधिकार नहीं है तो मामला अधिनियम की धारा 126 के तहत आएगा; उन पहलुओं के संबंध में भी जो इन दोनों प्रावधानों में अतिव्यापी हैं।इस स्थिति को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है।इसलिए यह स्पष्ट है कि यदि प्रत्यर्थियों/लाइसेंसधारी/आपूर्तिकर्ता के अधिकारियों की राय है कि कोई पुरुष अधिकार या धोखा देने का इरादा नहीं है, तो वे उपभोक्ता से ली जाने वाली राशि का आकलन करने के मामले में आगे बढ़ेंगे और फिर अधिनियम की धारा 126 और 127 के प्रावधान का पालन किया जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप अधिनियम की धारा 145 के तहत दीवानी अदालत की अधिकार क्षेत्र समाप्त हो जाएगी।

(29) तथापि, यदि उनका प्रथमदृष्टया यह विचार है कि; उन मामलों में भी जहां धारा 126 और 135 में उल्लिखित कारक अतिव्यापी हैं या उन कारकों पर जो अधिनियम की धारा 135 में विशेष रूप से उल्लिखित हैं, उपभोक्ता का विद्युत ऊर्जा निकालने का छलपूर्ण इरादा है; तो उन्हें या तो पुलिस या इस अध्याय के तहत गठित न्यायालय में शिकायत करने की आवश्यकता होगी।यदि मूल्यांकन अधिकारी/अधिकृत अधिकारी प्रथमदृष्टया यह विचार करता है कि मामले में चोरी शामिल है तो मूल्यांकन अधिकारी के पास चोरी के कारण हुए नुकसान की राशि या अपने स्तर पर जुर्माने का आकलन करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा।पुरुष अधिकार का तत्व चोरी के उद्देश्य के लिए एक अनिवार्य शर्त

है; इस मामले को विशेष रूप से अपराधों और दंड से संबंधित अध्याय द्वारा निपटाया जाएगा।निर्धारण अधिकारी को मूल्यांकन का आदेश देने के लिए कोई भी शक्ति देना, उन मामलों में भी जहां उपभोक्ता की ओर से निर्धारण अधिकारी/अधिकृत अधिकारी द्वारा चोरी का दावा किया जाता है; अपराधों और दंड से निपटने वाले अध्यायों के तहत गठित विशेष अदालत पर निर्धारण अधिकारी को पूर्व-निर्धारित शक्ति/अधिकार देने के समान होगा।यह कानून की नीति नहीं हो सकती और यह कानून का दर्शन नहीं हो सकता।एक बार जब मामला विशेष न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में स्पष्ट रूप से दिया जाता है, तो किसी भी मूल्यांकन अधिकारी/अधिकृत अधिकारी को अधिनियम के तहत गठित विशेष न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को पूर्व-खाली करने या किसी भी तरह से प्रभावित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इसलिए, यह स्पष्ट है कि एक बार जब विभाग या लाइसेंसधारी या आपूर्तिकर्ता द्वारा चोरी का आरोप लगाया जाता है तो मूल्यांकन अधिकारी/अधिकृत अधिकारी किसी विशिष्ट राशि की मांग करने वाले उपभोक्ता के खिलाफ कोई आदेश पारित नहीं कर सकता है, क्योंकि उस स्थिति में उपभोक्ता के खिलाफ देयता है। विशेष न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जाना।इसलिए, सवाल यह होगा कि यदि अभी भी मूल्यांकन अधिकारी/अधिकृत अधिकारी उपभोक्ता के खिलाफ मूल्यांकन/दंड/मांग का कोई आदेश पारित करते हैं तो ऐसे उपभोक्ता के लिए कहां और क्या उपाय उपलब्ध होगा।इस प्रश्न का उत्तर खोजते समय, यह ध्यान में रखना होगा कि न्यायालय एक न्यायालय है चाहे

उसके समक्ष पक्षकार उपभोक्ता हो या वह बिजली विभाग/लाइसेंसधारी/आपूर्तिकर्ता हो।इसलिए, इस प्रश्न पर विचार करते हुए कि क्या अधिनियम के तहत गठित विशेष न्यायालय सिविल न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को निहित रूप से बाहर करते हैं, यह देखना होगा कि क्या दोनों पक्षों को अधिनियम के प्रावधानों के तहत समान उपाय और अवसर दिए गए हैं ताकि वे विशेष अदालत के समक्ष अपने दावे को उठा सकें और उन पर निर्णय ले सकें और सिविल निर्णय के लिए निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार निर्णय ले सकें।

(30) जहाँ तक चोरी के मामले में बिजली विभाग/लाइसेंसधारी/आपूर्तिकर्ता के दावे का संबंध है, अधिनियम के भाग XIV द्वारा इसका ध्यान रखा गया है, जो अपराधों और दंड से संबंधित है।अधिनियम का अध्याय 135 चोरी को परिभाषित करता है और विभाग/लाइसेंसधारी/आपूर्तिकर्ता के अधिकारियों/अधिकारियों को जांच एजेंसी या अदालत को रिपोर्ट करने के लिए अधिकृत करता है; यदि उनका प्रथमदृष्टया यह विचार है कि उपभोक्ता ने चोरी की है।विभाग/लाइसेंसधारी/आपूर्तिकर्ता की इस शिकायत पर निर्णय लेने के लिए; अधिनियम का अध्याय XV विशेष अदालत के गठन के आधार पर एक विशेष मंच प्रदान करता है।विशेष न्यायालय चोरी के आरोप के संबंध में उपभोक्ता के अपराध का निर्धारण करने, उसे दंडित करने और अधिनियम के तहत प्रदान किए गए परिसमापन पैमाने पर उपभोक्ता के खिलाफ 'नागरिक दायित्व' का निर्धारण करके बिजली की

चोरी के कारण हुए नुकसान के लिए विभाग को क्षतिपूर्ति करने के लिए अधिकृत है।

(31) इस स्तर पर सवाल यह है कि विभाग द्वारा की गई अवैध और अनधिकृत मांग के खिलाफ उपभोक्ता को क्या उपाय मिला है?क्या अधिनियम की धारा 153 का प्रावधान जो विशेष न्यायालय के गठन का प्रावधान करता है, सिविल न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को रोकता है?क्या अधिनियम की धारा 154 के तहत विशेष न्यायालय को प्रदान की गई शक्ति नागरिक निर्णय का प्रावधान करती है, उपभोक्ता को विभाग द्वारा जबरन की गई अवैध मांगों के खिलाफ उपचार प्रदान करती है और इसलिए, निहितार्थ से, नागरिक न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बाहर करती है?अधिनियम की धारा 153 में प्रावधान है कि राज्य सरकार "अधिनियम की धारा 135 से 140 और धारा 150 में निर्दिष्ट अपराधों के मुकदमे के लिए" विशेष अदालत का गठन कर सकती है।अधिनियम की धारा 153 (1) यह स्पष्ट करती है कि अधिनियम के तहत गठित विशेष अदालत का गठन केवल धारा 135 से 140 तक के अपराधों पर निर्णय लेने के लिए किया गया है और अधिनियम की धारा 150; जैसा कि अधिनियम में विशेष रूप से उल्लिखित है। अतः, जिन मामलों में निर्धारण अधिकारी अधिनियम की धारा 126 के तहत आदेश पारित करने के लिए अधिकृत होने का दावा करता है और जिन मामलों में अधिनियम की धारा 143 के तहत आने का दावा किया जाता है, जहां न्यायनिर्णायक

अधिकारी किसी मामले पर निर्णय लेने के लिए अधिकृत है, वे अधिनियम की धारा 153 के तहत गठित विशेष न्यायालय के दायरे में नहीं आते हैं। इसलिए, अधिनियम की धारा 153 (1) के प्रावधान में उन मामलों के संबंध में दीवानी अदालत की अधिकार क्षेत्र को हटाने का प्रावधान नहीं है, जहां निर्धारण अधिकारी द्वारा मूल्यांकन या दंड का कथित आदेश पारित किया जाता है, हालांकि गलत तरीके से, अधिनियम की धारा 126 के तहत ऐसा आदेश पारित करने का उसका अधिकार है।

(32) अधिनियम की धारा 154 के प्रावधान से यह स्पष्ट है कि यह उपभोक्ता को विभाग के खिलाफ अपने दावे को स्थापित करने के लिए कोई उपाय प्रदान नहीं करता है और न ही यह किसी मामले के नागरिक निर्णय के सिद्धांतों के अनुसार नागरिक निर्णय के किसी भी तंत्र का प्रावधान करता है।अधिनियम की धारा 154, जो विशेष न्यायालय की शक्तियों को परिभाषित करती है, इसे अधिनियम की धारा 135 से 140 और धारा 150 के तहत आने वाले मामलों तक सीमित करती है। यह धारा विशेष अदालत को केवल एक सत्र न्यायालय की शक्तियां प्रदान करती है और केवल दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में, 'Cr.P.C') के खिलाफ एक गैर-बाधा धारा का उपयोग करती है, न कि सिविल प्रक्रिया संहिता (संक्षेप में, 'CPC') के खिलाफ।इसलिए, अधिनियम की धारा 135 से 140 और धारा 150 के तहत परिभाषित अपराधों के अलावा अन्य मामलों में सी. पी. सी. के अनुप्रयोग को अधिनियम की धारा 154 द्वारा

बाहर नहीं रखा गया है। इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति के कथित अपराध के निर्धारण से परे, अभियुक्त सी. पी. सी. के तहत अपने नागरिक उपचारों का बहुत अच्छी तरह से लाभ उठा सकता है यदि उसका दावा उपरोक्त धाराओं द्वारा निर्दिष्ट अपराध के अलावा अन्य है।फिर भी अधिनियम की धारा 155 के एक नंगे अवलोकन से पता चलता है कि विशेष न्यायालय को सत्र न्यायालय माना जाएगा और उसके पास सत्र न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी।इसके अलावा यह निर्धारित करता है कि विशेष न्यायालय के समक्ष अभियोजन का संचालन करने वाले व्यक्ति को लोक अभियोजक माना जाएगा।इसके अलावा, अधिनियम की धारा 156, जो अपील और संशोधन का प्रावधान करती है, यह भी निर्धारित करती है कि उच्च न्यायालय विशेष न्यायालय के आदेश के खिलाफ शक्तियों का प्रयोग कर सकता है जैसा कि सत्र न्यायालय के आदेश से Cr.P.C के तहत उसे प्रदान किया गया है।इन प्रावधानों के संयुक्त अध्ययन से पता चलता है कि अधिनियम के तहत गठित विशेष न्यायालय को दीवानी न्यायालय के रूप में कार्य करने की कोई शक्ति नहीं दी गई है, दीवानी न्यायालय के प्रावधानों के अनुसार मामले को संचालित करने की शक्ति नहीं दी गई है।इसलिए किसी भी तरह की कल्पना से, न तो अधिनियम के तहत गठित विशेष अदालत दीवानी अदालतें हैं और न ही ये अदालतें पक्षों के नागरिक अधिकारों का निर्धारण करती हैं। इन अदालतों का मतलब है, विशेष रूप से, किसी अभियुक्त पर

मुकदमा चलाना और इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ऐसे अभियुक्त को सजा देना।

(33) अधिनियम के प्रावधानों और योजनाओं के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि यदि निर्धारण अधिकारी किसी उपभोक्ता को निर्धारित राशि और/या जुर्माने के लिए मांग सूचना भेजता है और उसी समय चोरी का आरोप भी लगाता है तो उपभोक्ता के पास उस मांग/मूल्यांकन को चुनौती देने का कोई उपाय नहीं है, हालांकि निर्धारण अधिकारी द्वारा की गई ऐसी मांग/मूल्यांकन पूरी तरह से अधिकार और अधिकार क्षेत्र के बिना है।विशेष अदालत उपभोक्ता पर मुकदमा चलाने के लिए विभागों/लाइसेंसधारी/आपूर्तिकर्ता के लिए उपलब्ध एकतरफा मंच हैं।ये अदालतें किसी भी परिस्थिति में उपभोक्ता के पक्ष में कोई डिक्री नहीं दे सकती हैं।जहाँ तक संभावित का संबंध है; उपभोक्ता के दृष्टिकोण से, विशेष अदालत के पास अधिनियम में निर्दिष्ट अपराधों के लिए उपभोक्ता पर मुकदमा चलाने और उपभोक्ता को दंडित करने का बहुत सीमित जनादेश है।भले ही अधिकारियों/लाइसेंसधारी/आपूर्तिकर्ता द्वारा पारित आदेश पूरी तरह से अवैध हो, उपभोक्ता को अधिनियम के तहत गठित विशेष अदालत से संबंधित किसी भी प्रावधान के तहत ऐसे आदेश को चुनौती देने के लिए कार्यवाही शुरू करने का कोई उपाय नहीं दिया गया है। न ही इस अधिनियम के तहत गठित विशेष अदालत को उपभोक्ता द्वारा किसी आदेश के खिलाफ शुरू की गई किसी भी याचिका पर विचार

करने की शक्ति दी गई है, जिसे वह अपने नागरिक अधिकारों का उल्लंघन मान सकता है।इसलिए, किसी भी तरह से, विशेष अदालत का निर्माण, विशेष अदालत को प्रदत्त अधिकार क्षेत्र या उनके अधिकार का दायरा उपभोक्ता के दावे के निर्धारण को नहीं समझता है; जैसा कि उपभोक्ता द्वारा और उपभोक्ता के दृष्टिकोण से शुरू किया गया है।उक्त विशेष न्यायालयों के संविधान के प्रावधानों के तहत; अधिकारियों/लाइसेंसधारी/आपूर्तिकर्ता द्वारा कार्यवाही शुरू करने और अभियोजन एजेंसी/विभाग के अधिकारी/लाइसेंसधारी/आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत मामले के अनुसार उसके निर्धारण की दया पर उपभोक्ता को पूरी तरह से आपराधिक अधिकार क्षेत्र में धकेल दिया गया है।उनके पास इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत विभाग द्वारा प्रस्तुत और अभियोजित तरीके से और आपराधिक अदालत द्वारा तय किए गए तरीके से अपने भाग्य के फैसले की प्रतीक्षा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

(34) अधिनियम की धारा 154 (5) के प्रावधान पर यह तर्क देने के लिए बहुत जोर दिया गया है कि विशेष न्यायालय को उपभोक्ता या किसी व्यक्ति के खिलाफ 'नागरिक दायित्व' निर्धारित करने की शक्ति दी गई है; ऊर्जा की चोरी के लिए धन के संदर्भ में, इसलिए, अधिनियम की धारा 145 के प्रावधान को अधिनियम की धारा 154 के निहितार्थ और व्याख्या द्वारा दीवानी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बाहर करने के रूप में पढ़ना होगा। यह एक बुनियादी भ्रांति है तक कि इस प्रावधान के नंगे अवलोकन

से भी पता चलता है कि विशेष न्यायालय केवल उपभोक्ता के खिलाफ नागरिक दायित्व निर्धारित कर सकता है।इसके पास उपभोक्ता के 'पक्ष में' नागरिक दायित्व निर्धारित करने की कोई शक्ति नहीं है।उपभोक्ता के खिलाफ 'नागरिक दायित्व' तय करने के लिए इस प्रावधान को लागू करने का कारण यह है कि किसी व्यक्ति को चोरी के अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने के बाद ही इस उप-धारा को लागू करने की आवश्यकता है।इसलिए, अधिनियम की धारा 154 (5) के तहत 'नागरिक दायित्व' विभाग को दिए जाने वाले धन के संदर्भ में अतिरिक्त दंड की प्रकृति का है, इसके अलावा अधिनियम में अन्यथा प्रदान किए गए कारावास और जुर्माने की सजा भी है। यह तथ्य कि नागरिक दायित्व का यह निर्धारण 'सजा' के माध्यम से होता है, इस तथ्य से भी परिलक्षित होता है कि इसे 'न्यूनतम' 'मौद्रिक' सजा के रूप में प्रदान किया गया है।विशेष न्यायालय 'नागरिक दायित्व' को निर्धारित करने के लिए अधिकृत नहीं है जो चोरी की अवधि के लिए 'शुल्क का दो गुना' राशि से कम या उसके बराबर नहीं है।यदि अधिनियम द्वारा इसे 'नागरिक दायित्व' के रूप में माना जाता, जैसा कि नागरिक अधिकार क्षेत्र में विचार किया गया है, तो न्यूनतम दायित्व तय करने का कोई सवाल ही नहीं होता और यहां तक कि मुकदमे में केवल एक पक्ष के खिलाफ भी।यद्यपि सिविल दायित्व, जैसा कि विशेष न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जाता है, को सिविल न्यायालय की एक मानित डिक्री घोषित किया जाता है, तथापि, सिविल दायित्व को विशेष न्यायालय द्वारा सिविल न्यायालय की डिक्री के रूप में निर्धारित करने की

यह काल्पनिक कल्पना, केवल वसूली के उद्देश्य के लिए सीमित है; हानि या क्षति के रूप में; जैसा कि विशेष न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया है कि उपभोक्ता द्वारा विभाग को किया गया था, लेकिन पूर्व निर्धारित पैमाने के अनुसार।लेकिन यह स्पष्ट तथ्य कि उक्त 'नागरिक दायित्व' का निर्धारण करने में न तो नागरिक प्रक्रिया का पालन किया गया है और न ही इसे एक नागरिक न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया है, 'नागरिक दायित्व' के इस तरह के निर्धारण को उपभोक्ता के दायित्व का अंतिम निर्धारण नहीं माना जा सकता है और न ही इसे अधिनियम द्वारा उपभोक्ता के खिलाफ अंतिम निर्धारण घोषित किया गया है।'नागरिक दायित्व' का ऐसा निर्धारण और 'डिक्री' के रूप में एक काल्पनिक कल्पना का निर्माण विभाग/लाइसेंसधारी/आपूर्तिकर्ता को उन साधनों द्वारा से इस राशि की वसूली करने में सक्षम बनाने तक सीमित है जिनद्वारा से एक डिक्री निष्पादित की जाती है।हालाँकि, यह तथ्य स्वयं किसी उपभोक्ता को विशेष न्यायालय द्वारा निर्धारित अपने दायित्व को चुनौती देने से नहीं रोकता है, यहां तक कि एक दीवानी अदालत के समक्ष देश के नागरिकों के लिए सी. पी. सी. द्वारा निर्धारित दीवानी प्रक्रिया का पालन करने पर जोर देकर और दीवानी कानून में लागू सबूत के मानक के अनुसार यह कहना कि अन्यथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 द्वारा गारंटीकृत उस नागरिक के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा।अन्यथा, यह भी एक स्थापित कानून है कि जबकि दीवानी अदालत द्वारा पारित डिक्री पर बाध्यकारी हो सकती है। आपराधिक अदालत लेकिन आपराधिक अदालत

का एक निर्णय या आदेश एक दीवानी अदालत पर बाध्यकारी नहीं है।केवल यह तथ्य कि आपराधिक न्यायालय के आदेश को दीवानी न्यायालय की डिक्री का रंग या मानित दर्जा दिया गया है, कानून के इस तय किए गए प्रस्ताव को नहीं बदलता है।न्यायालय के किसी आदेश के सिविल डिक्री होने के पूर्ण प्रभाव के लिए, नागरिक प्रक्रिया द्वारा से और सिविल कानून के सिद्धांतों के अनुसार इसका निर्धारण करना सार है।आपराधिक कानून द्वारा से किसी भी निर्धारण का नागरिक कानून द्वारा से निर्धारण का पूरा प्रभाव या बहिष्कार नहीं हो सकता है क्योंकि आपराधिक निर्धारण में एक पक्ष, यानी आरोपी हमेशा सजा के खतरे में होता है, वह अभियोजन के खिलाफ अपने बचाव के प्रति पूर्वाग्रह के डर से अपनी सभी दलीलें भी नहीं उठा सकता है और उसे अधिकार है; यहां तक कि चुप रहने का भी।इसलिए आपराधिक प्रक्रिया द्वारा से निर्धारण नागरिक प्रक्रिया द्वारा से निर्धारण को बाहर नहीं कर सकता है।आखिरकार, किसी नागरिक को कानूनी रूप से ऐंठन के अधीन होने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।

(35) अतः उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि विभाग के अनधिकृत अधिकारी/लाइसेंसधारी/आपूर्तिकर्ता द्वारा की गई अवैध मांग के मामले में उपभोक्ता को अधिनियम के तहत कोई उपाय नहीं दिया गया है। हालांकि, चोरी के अपराध की सुनवाई करने और आरोपी/दोषी के 'नागरिक दायित्व' के माध्यम से विभाग को हुए नुकसान का निर्धारण करने के लिए विशेष

अदालत का गठन किया गया है, हालांकि, विशेष अदालत को दीवानी अदालत की कोई शक्तियां नहीं दी गई हैं।विशेष न्यायालय में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया दीवानी न्यायालयों के लिए नहीं है।विशेष अदालत को प्रदान की गई शक्तियां दीवानी न्यायालयों को प्रदान की गई शक्तियां नहीं हैं और अधिनियम के तहत विचार किए गए निर्णय का दायरा नहीं है, जो कि दीवानी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के मामले में स्पेक्ट्रम का है।इसलिए यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि विशेष न्यायालय का गठन, उसे प्रदत्त शक्तियां या इन न्यायालयों द्वारा निपटाए जाने वाले मामलों का दायरा उपभोक्ता को दीवानी विवादों को उठाने और दीवानी प्रक्रिया द्वारा से या 'उसके पक्ष में' निर्णय लेने के लिए उपाय प्रदान नहीं करता है।अधिनियम की धारा 153 के तहत गठित विशेष अदालतें केवल अधिनियम की धारा 135 से 140 और धारा 150 के तहत उल्लिखित अपराधों की सुनवाई के लिए हैं। चूँकि विशेष अदालत का दायरा अपने आप में उपभोक्ता के नागरिक अधिकारों के उपचार और निर्धारण को शामिल नहीं करता है; जो कि अवैध और अप्रचलित आदेशों से पारित हो सकते हैं या मूल्यांकन अधिकारी या न्यायनिर्णायक अधिकारियों द्वारा उनकी शक्तियों के दायरे से परे की गई कार्रवाई से उत्पन्न हो सकते हैं, इसलिए यह माना जाना चाहिए कि निहितार्थ से भी, सिविल न्यायालय की अधिकार क्षेत्र को बाहर/वर्जित नहीं किया गया है, जैसा कि अधिनियम की धारा 145 के तहत विचार किया गया है, केवल अधिनियम के तहत विशेष अदालत के गठन के कारणों से।

(36) इस मामले में विचार करने के लिए अगला सवाल यह है कि क्या दीवानी अदालत के अधिकार क्षेत्र को अदालतों द्वारा वादकारी को एक वैकल्पिक विधि या अधिनियम द्वारा कथित रूप से प्रदान की गई अपील के वैकल्पिक उपचार का सुझाव देकर केवल साइड ट्रैक किया जा सकता है?इस प्रश्न का उत्तर नकारात्मक होना चाहिए; सी. पी. सी. की धारा 9 के प्रावधान को ध्यान में रखते हुए जो दीवानी अदालतों को किसी भी मुकदमे का मुकदमा चलाने के लिए योजना बनाने की शक्ति देता है और सी. पी. सी. के आदेश । नियम । के प्रावधान किसी भी व्यक्ति को दीवानी मुकदमा दायर करने का अधिकार देते हैं, अगर वह अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति की किसी भी कार्रवाई से पीड़ित है, तो अपने नागरिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।अन्यथा भी, अधिनियम की धारा 126 के प्रावधान से पता चलता है कि इस प्रावधान के तहत यह निर्धारण अधिकारी का "सर्वश्रेष्ठ मूल्यांकन निर्णय" है; जो निर्णय और निर्णय के लिए आधार होगा, यदि अधिनियम की धारा 127 के तहत अपील की जाती है। यहाँ तक कि निर्धारण की अवधि और दर भी अधिनियम के प्रावधानों से ही बंधी हुई है।इसलिए, यदि किसी उपभोक्ता को निर्धारण अधिकारी के अनधिकृत आदेशों के खिलाफ अपील का उपाय करना है, तो चुनौती इसके दायरे और अधिकारों में सीमित होगी।अधिकारों और निर्णय का ऐसा सीमित दायरा योजना निर्धारण का विकल्प नहीं है, जिसके लिए एक नागरिक हकदार होगा, यदि वह एक दीवानी अदालत के समक्ष एक स्वतंत्र मुकदमा लाता है।इसलिए केवल इसलिए कि एक उपभोक्ता को

अधिनियम की मुकदमा 127 के तहत अपील के उपचार का लाभ उठाने का सुझाव दिया जा सकता है, अन्यथा अनधिकृत, आदेश के खिलाफ, यह मानने का कोई आधार नहीं है कि वह दीवानी अदालत के दीवानी अधिकार क्षेत्र को लागू करके दीवानी मुकदमे के उपचार का लाभ नहीं उठा सकता है।अधिनियम की धारा 126 और 127 को उनके दायरे तक सीमित रखना होगा जैसा कि अधिनियम के प्रावधानों द्वारा उन्हें सौंपा गया है। इन प्रावधानों की भाषा को शब्दों या वाक्यांशों के साथ अंतःस्थापित किए जाने के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है ताकि उन मामलों को भी इसके दायरे में लाया जा सके जिन पर इन धाराओं के केवल प्रावधानों द्वारा विचार नहीं किया गया है।अन्यथा चोरी के आरोप के मामले में भी निर्धारण अधिकारी के आदेश को अधिनियम की धारा 127 के तहत अपील मुकदमा ठहराना, उस मामले में भी ऐसे निर्धारण अधिकारी की कार्रवाई को कानूनी पवित्रता देने के समान होगा, जिसे विशेष न्यायालय केवल अधिनियम के तहत निर्धारित करने के लिए अधिकृत है। इसलिए, एक ऐसे मामले में जो अधिनियम की धारा 126 और 127 के दायरे में सख्ती से नहीं आता है, जैसा कि चोरी के आरोप के मामले में, एक उपभोक्ता/नागरिक को अधिनियम की धारा 127 के तहत अपील के वैकल्पिक उपाय का सुझाव देकर दीवानी अदालत के समक्ष दीवानी मुकदमे का लाभ उठाने के उसके अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है।

(37) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, इस मामले में शुरुआत में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार होने चाहिएः

(1) यदि विभागों/अधिकारियों/लाइसेंसधारी/आपूर्तिकर्ता की राय है कि किसी उपभोक्ता ने अधिनियम के तहत परिभाषित चोरी की है, और वे अधिनियम की धारा 135 के तहत चोरी के लिए कार्यवाही शुरू करते हैं, तो मूल्यांकन अधिकारी को उपभोक्ता के खिलाफ दायित्व और दंड के आकलन के संबंध में कोई आदेश पारित करने का कोई अधिकार नहीं है।यदि मूल्यांकन/जुर्माने का ऐसा कोई आदेश पारित किया जाता है और विभाग/लाइसेंसधारी/आपूर्तिकर्ता द्वारा किसी उपभोक्ता के खिलाफ कथित रूप से लागू किया जाता है, तो उपभोक्ता को विभाग/लाइसेंसधारी/आपूर्तिकर्ता द्वारा उठाए गए ऐसे आदेश/मांग को चुनौती देकर दीवानी मुकदमे का लाभ उठाने का मुकदमा अधिकार है।ऐसी स्थिति में, दीवानी न्यायालय की अधिकार क्षेत्र अधिनियम की धारा 145 के आधार पर बाधित नहीं होगी।

(2) यदि चोरी का आरोप लगाने और कार्यवाही शुरू करने के बावजूद विभाग/लाइसेंसधारी/आपूर्तिकर्ता द्वारा मूल्यांकन/जुर्माने का अनधिकृत आदेश पारित किया जाता है, तो उपभोक्ता को अधिनियम की धारा 127 के तहत वैकल्पिक उपाय नहीं कहा जा सकता है। इसलिए, उसे इस आधार पर इस तरह के अवैध मूल्यांकन/मांग/जुर्माना नोटिस के खिलाफ दीवानी मुकदमा दायर करने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता

है कि वह अधिनियम की धारा 127 के तहत अपील के वैकल्पिक उपाय का लाभ उठा सकता है।

(3) चूंकि उपभोक्ता के कहने पर विशेष न्यायालय की शुरुआत नहीं की जा सकती है और विशेष अदालत द्वारा निर्धारित नागरिक दायित्व को केवल उपभोक्ता के खिलाफ और केवल विभाग को हुए नुकसान/नुकसान के लिए निर्धारित करने के लिए प्रतिबंधित किया गया है और यहां तक कि एक दीवानी अदालत की प्रक्रिया का पालन किए बिना भी, इसलिए, केवल विशेष न्यायालय का अस्तित्व, निहितार्थ से, दीवानी अदालत की अधिकार क्षेत्र को बाहर नहीं करता है, ऐसे मामले में जहां निर्धारण अधिकारी/लाइसेंसधारी/आपूर्तिकर्ता ने मामले को पुलिस या विशेष अदालत को भेजने के बावजूद अवैध या अनधिकृत मांग का आदेश पारित किया है।

(38) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान मामले में निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश में एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। 1,49,200-अभियोक्ता पर, प्रतिवादी द्वारा दीवानी न्यायालय के समक्ष सही चुनौती दी गई थी।नीचे दिए गए न्यायालयों ने वर्तमान प्रतिवादी द्वारा मुकदमा मुकदमे का सही फैसला सुनाया है।प्रतिवादी के पास विशेष अदालत के समक्ष इस तरह के जुर्माने के खिलाफ कोई दावा दायर करने के लिए कोई उपाय उपलब्ध नहीं था। निचली अपील न्यायालय ने ठीक ही

अभिनिर्धारित किया है कि दीवानी अदालत को मामले का परीक्षण करने और उसी पर निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र मिला है।

(39) कोई अन्य तर्क नहीं उठाया गया।

(40) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, निचली अपील न्यायालय द्वारा पारित निष्कर्षों और डिक्री को बरकरार रखा जाता है।वर्तमान अपीलकर्ता द्वारा दायर अपील योग्यता से रहित होने के कारण खारिज कर दी जाती है।

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निणर्य वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्येश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्येश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

(नरेंदर)
ट्रांसलेटर
कोर्ट ऑफ़ श्री के. पी. सिंह,
एडिशनल सेशंस जज, भिवानी !